

आपने स्वाध्यायों को समझाते हुए भी दिखते कि वे आमरण अनशन समाज के दायें दायें बेंच में उड़लवाने की ओर से पेश केल्ले गमिन्दार को गिल से अदालत में कहा कि आपको यह जेल या रज्जवा बाहरिए कि जना को आदलत से अयुक्तियान न हो।

बेंच में बैठे, एक लोकावर्तिका व्यवस्था में आपको शास्त्रिण पदमन का पूरा अधिकार है, लेकिन यही ध्यान रखना बाहरिए कि जना को इससे अयुक्तियान हो। आप समी पताज के हैं कि खान्नी बॉर्डर पंजाब के लिए लाहलपनाव की तरह है। हम यह नहीं कहते हैं कि प्रचुरी सही है या गलत, लेकिन जना को प्रचुरी नहीं हमोने कहा। जेजिस प्रचुरी नही हमोने बाहरिए कि उदललत प्रदमनकारियोंका यह समझा करेते हैं कि वे शास्त्रिणों आदलत करेते, यह ध्यान रखे कि उनके प्रदमन से आप लोकावर्तिका उदललत न हो।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

## भारतीय बस्ती

बस्ती 3 दिसम्बर 2024 मंगलवार

### सम्पादकीय

#### बांग्लादेश में हाशिये पर हिन्दू

1971 की भारत पाक جنگ के बाद हिंदुस्तान की बदौलत नज़ूद में आए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव हमारे देश के लिए निरंतर चिंता का सबब बना हुआ है। जनसंख्या के लिहाज से, बांग्लादेश भारत और नेपाल के पड़ोसी देशों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 61 में हिंदू धर्म हिंदू सार्वसे बड़ा धर्म है, लेकिन बांग्लादेश में कोई हिंदू बहुल जिला नहीं है। वर्तमान बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में घट रही है, 1941 में 28 प्रतिशत से 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के समय 13.5 प्रतिशत हो गई और 2022 में और कम होकर 7.9 प्रतिशत हो गई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान उन्नीडन से बचने के लिए लगभग 80 लाख हिंदू भारत के विभिन्न हिस्सों में भाग गए। आजादी के बाद, यह पता चला कि 15 लाख हिंदू भारत में रह गए।

ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री अबुल बरकत के अनुसार, 1964 से 2013 तक धार्मिक उन्नीडन और भेदभाव के कारण लगभग 11.3 मिलियन हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया। उनके अनुसार औसतन हर दिन 632 हिंदू देश छोड़कर चले गए और पाकिस्तान 230,612 हिंदू देश छोड़कर चले गए। पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी नहीं नहीं है। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, लाखों की संख्या में हिंदू और मुसलमानों ने धर्म के आधार पर मुल्क बदला। फिर भी कुछ मुसलमान ऐसे थे, जो भारत में ही रह गए और इसी तरह कुछ हिन्दू पाकिस्तान में रह गए। भारत ने हिन्दू राष्ट्र बनने की बजाय धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना पसंद किया, ताकि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित न समझें, उन्हें समान अधिकार मिलें और इसके लिए भारत ने अपने संविधान में धर्म चुनने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया है।

भारत विभाजन से पहले मुसलमानों की संख्या भारत की कुल आबादी का 10 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की किस्मत भारतीय मुसलमानों जैसी न तब थी, न आज है। पाकिस्तान में बसे हिन्दुओं में से लगभग 96 फीसदी सिंध प्रान्त में ही रहते हैं। वर्ष 1956 में पाकिस्तान की संविधान बना और पाकिस्तान प्रतिशील और उदारवादी विचारधारारों को त्यागकर कट्टर देश बन गया, और तभी से अल्पसंख्यक हिन्दुओं का वहां रहना दुश्वार हो गया। बांग्लादेश में भी यह कहानी दोहराई जा रही है। देखने में आया है कि पाकिस्तान की जब भी भारत के आगे दाल नहीं गलती तो सभी घटनाओं का दुष्परिणाम पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को भुगतान पड़ता है। जिया-उल-हक की तानाशाही से लेकर अब तालिबान के अत्याचारों तक पाकिस्तानी हिन्दुओं का जीवन दूसर ही रहा है।

कहते हैं कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, जिनमें से अब सिर्फ 26 ही बचे हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर हिन्दू मंदिर या गिरा दिए गए या उन्हें होटल बना दिया गया है। पाकिस्तान के नेशनल कमिशन फॉर जस्टिस एंड पीस की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक 74 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में हर महीने 20 से 25 हिन्दू लड़कियां यौन अपहरण होता है और जबदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जब पाकिस्तान में जीने के लिए हिन्दू अल्पसंख्यकों की अनुकूल स्थिति नहीं रहे, तो बांग्लादेश इन्फका अपवाद केसे साबित होगा और आज यही कुछ हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है।

बांग्लादेश की वर्तमान सरकार भारत विरोधी सोच वाली है जिससे युनुस भी अछूते नहीं हैं। अगर वे भारत हितैषी दिखना भी चाहें तो वह ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हत्तीना सरकार के गिरने का बड़ा कारण उनका भारत हितैषी नजरिया था। वर्ना वह बड़ा सुप्रीमकोर्ट का रिजर्वेशन पर फैसला आने के बाद उनको अपदस्थ करने का कोई कारण ही नहीं था? रिजर्वेशन के नाम पर वहां के युवाओं को हथियार के रूप में बांग्लादेशी कट्टरशायियों ने इस्तेमाल किया और हत्तीना सरकार को गिरा दिया। ये लोग ऐसे अवसर की तलाश में ही बैठे थे। खेद की बात है कि जिस बांग्लादेश को आज कादर के लिए हिंदुस्तानी यानी भारतीय फौजों ने मुकाबला किया था, इसी भारत के बहुसंख्यकों को अब वहां के हुक्मरान अपना दुश्मन क्यों मानते हैं?

## सियासत के नये समीकरण में प्रियंका गांधी



—ज्योति मल्होत्रा—

पिछले सप्ताह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में छाई गहरी खामोशी आपको बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा देश भर में सत्ता क्यों कायम रखे हुए हैं। एक शब्द में कहें तो ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस उन्हें इसके लिए सक्षम बनाती है।

पिछले छह-सात दिनों से खूब खबरें चली कि महाराष्ट्र के महापुति गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर खीलतान और दबाव बना हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। इसके विपरीत, कांग्रेस फिर से कवरल लेकर सोने चूरी गई लगती है। एमपीए गठबंधन से उजड़ ठाकरे द्वारा किलाना करने की चर्चा राज्य में हो रही है, लेकिन गठबंधन में घटकों के बीच दरार और मनमुटाव का शोर वास्तव में चुनाव परिणाम आने से पहले ही मचना शुरू हो गया था जब वे इस मुद्दे पर बहस करने लगे थे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा?

निश्चित रूप से, यह एक अनूठी स्थिति है। कांग्रेस और राहुल गांधी



नियमित रूप से भाजपा पर मोदी की छवि बतौर देवतुल्य व्यक्ति पेश करने का आरोप लगाते हैं दृष्ट प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पहले वाराणसी में एक चीनल को दिए साक्षात्कार में इस तथ्य को स्वीकार किया था, जब उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भाजपा ने (मुझे) भेजा है, क्योंकि इतनी ऊर्जा में जैविक शरीर में तो नहीं हो सकती थी। लेकिन तथ्य यह है कि भले ही कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है दृष्ट आरक्षित नियम की बजाय लगाव है दृष्ट फिर भी उसने अपने अंदर श्रद्धांजलि से आंखें मूंद रखी हैं।

आश्चर्यजनक तथ्य यह बना हुआ है कि हार के पीछे राहुल गांधी पर सीधे-सीधे अंगुली उठाने से कांग्रेस पार्टी बचती है और यह बात मोदी और भाजपा को राज्य-दर-राज्य खुद को मजबूत करने का मौका प्रदान करती है। जब पिछली गर्मियों

में भाजपा संसद में अपना खुद का पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई थी, तो उसने बांधी की से जॉय की गलती कहाँ रही, जिसमें यह भी शामिल था कि आरएसएस ने मदद क्यों नहीं की। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में मूल से सबक लेना सुनिश्चित किया गया दृष्ट इसलिए हरियाणा में प्रत्येक किनासा सीट पर माइकों मैनेजमेंट की गयी और अति आत्मविश्वासी भी कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली और महाराष्ट्र में लाइली-बहना जैसी योजनाओं की बदौलत जीत हासिल की, जो मिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसों डाकने की गारंटी देती है।

इसके विपरीत, कांग्रेस इंदीएन को दोष देने में लगी रही और अपनी विफलता के पीछे बड़े पैमाने पर ढांढी को जिम्मेदार ठहराया। तमाम अक्षे तलाओं की तरह विफलता को स्वीकार करने के बजाय राहुल

वापनाड से अपनी करिश्माई बहन की जीत मानने में अगुवाई करते नजर आए दृष्ट मनोहरा खासाकर जब वह युवा महिला पारंपरिक करल कसापु साड़ी में संसद में शपथ लेने पहुंची और जुट्टिहिन हिंदी में संसद के रूप में सौभाग्य उचिता। लेकिन अब वास्तविक दृष्ट देखिये। सदन में अब तीन गांधी हैं—राज्यसभा में मां सोनिया तो लोकसभा में उनके बच्चे राहुल और प्रियंका, राहुल उत्तर प्रदेश के दिल रायबरेली से सांसद, तो प्रियंका दक्षिण भारत के खूबसूरत पहाड़ी जिले वायनाड से। लेकिन यहां कोई मुगलाना न रहे, इस जीत से पारिवारिक जागीर लूरी कांग्रेस पर गांधियों की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई है।

वंशवाद विरोधी आवाजे उठना भारतीय राजनीति में अब लंबे समय से बंद हो चुकी हुई आज न केवल कांग्रेस बल्कि हर राजनीतिक दल, नेता-नेत्रियों के बेटे-बेटियों से

भरा पड़ा है, जो कथित तौर पर अखाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पीछे वे कौन से तर्क देते, उनसे अब हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। भारत के लोग इतने अवलमर्द हैं कि अगर आप उनके लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करते तो वे आपको अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही आपकी बंपोती कितनी भी बतती हो। वंशवाद का आरोप अब कांग्रेस की समस्या नहीं रही। यह तथ्य है कि गांधी परिवार ने एक मुखौटे पर जोर देना जारी रखा हुआ है, मुखौटा पहने उस आदमी की डोर पीछे से इस परिवार के हाथ में है। बतौर सांसद अपनी पदोन्नति के साथ, प्रियंका कठपुतली चलाने वालों की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। उनकी मां, एक असाधारण महिला, जिन्होंने साल 1991 की गर्मियों में अपने पति की दुखद और जघन्य हत्या के बाद बनी परिस्थिति में कांग्रेस के कुनबे को एकजुट बनाए रखा और मनमोहन सिंह के उल्लेखनीय नेतृत्व में कांग्रेस 10 साल में रही। वे अब सार्वजनिक जीवन से दूर हो गई हैं, उनकी बेटी ने आगे आकर मोर्चा संभाला है।

यह अप्रासंगिक है कि कमान किसके हाथ में दी गई है, सोनिया के बेटे को या बेटी को। सदन में बतौर नए प्रभु, प्रियंका की अनुपस्थिति पहाड़ी उपस्थिति घटनाएं बताती हैं कि गांधियों को हलके में लेना आसान न होगा। यदि कारण है कि प्रियंका को इतना महत्व है। वे पार्टी में जंग भरने और राजनीति में हलचल मचाने का मादा रहती हैं। तब ही जब वे संसद में बोलेगी तो माहौल में बिजली अस्थिर दौड़ जाएगी। हालांकि, इस बात की गुंजाइश कम है कि कांग्रेस की डोलती नया को वे

पार लगा पाएंगी, क्योंकि पतवार भाई के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों जगह, गठबंधन को मिली वोटों का हिस्सा घटिया है। या फिर भाई-बहन की जोड़ी इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को लेकर सहज है दृष्ट जैसा कि गणतुल्य कांग्रेस ने अनुरोध किया है कि संसद को इस शीतकालीन सत्र में काम करने दिया जाए दृष्ट बजाय इसके कि अडानी मुद्दे पर राहुल अड़े रहें।

सब ठीक होता यदि कांग्रेस कुछ राज्यों में जीत जाती दृष्ट आखिरकार, हर कोई विजेता को पसंद करता है। लेकिन जब पार्टी लगातार हार रही हो, तो सवाल यह पैदा होता है कि गांधी परिवार इतना खास क्यों है कि उसे चुनौती दी जा सके दृष्ट जैसा कि जी-23 ने एक बार संघभक्त प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं दृष्ट इसका जवाब अभी भी ठीक से नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से, इस घटनाक्रम से मोदी से ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा। वे जानते हैं कि जब वे पार्टी के अंदर लड़ने वाली की कमी के लिए कांग्रेस पर रज कर सकते हैं, तो लाखों भारतीयों के दिलों को खून है। वे जानते हैं, और देश की जून है कि, इंडिया जगह इंदिरा के दिन बहुत पहले लड़ चुके हैं। और यदि गांधी परिवार जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, तो यह पुरानी छड़ी पार्टी थोड़े-थोड़े घटने के लायकी। एक सप्ताह पुराने अखंड दिनों में, प्रियंका को कांग्रेस पार्टी का ब्रह्मचर्य कहा जाता था।

सवाल यह है कि क्या ऐसा हथियार आजागी राजनीति में कुछ कर दिखाएगा।—लेखिका दृष्ट ट्यून्स की प्रधान सम्पादक हैं।

#### कैसे मजबूत

#### —प्रहलाद सबनानी—

भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अव्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की चर्चा जरूरी बहुत कम ही रही है। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई देती हैं। देश की अव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आकार का बनाया है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब सहकारिता से सम्बंधी की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है।

भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 65 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक इस्फका सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए हैं। उत्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी संस्थाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में मिलल सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी

#### बने सहकारिता आंदोलन



संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं। इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में युनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं। इनकी संख्या लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

उत्तमोक्ति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक सहकारी बैंक बैंक नितीकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उत्त समस्त आंकड़ों वर्ष 2021-22 तक के हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिति लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई है, जिससे आज भी सहकारी रूप में निरंतर बड़ी सफलता के रूप में जाना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा भोजनार्थ के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में समानांतर विनियम सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित स्तर पर कोई संस्करण नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक

एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणालि पर हमला से ही आरोप लगाते रहे हैं एवं कई तरह की शंकाओं की छद्मनायक समय समय पर उभारना होती रही है। इसके विपरीत सहकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सज्जिव रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की विशेष नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास गति अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में विशेष प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूर्ण बाजार से पूर्ण जुड़ा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक कुछ सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसौट आयागी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिससे चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा।

सहकारी क्षेत्र पर आबर्तित आर्थिक मोडेल के कई लाभ हैं जो नई प्रकार की चुनौतियों में भी मुख्य चुनौतियां जिला इलाकों में कार्य कर रही जिला क्षेत्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं के समाने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की र्थीम बहुत पुरानी है। ये बैंक के साथ इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सका है। जबकि आज के ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर भी बढ़ता गया है। ग्रामीण इलाकों में अब केवल 35 प्रतिशत आय कृषि आधारित कार्य कर रही है शेष 65 प्रतिशत आय ग्रं कृषि आधारित कार्यों से होती है। अतः ग्रामीण इलाकों में कार्ग कर रहे इन बैंकों को अब नए व्यवसाय माडल खोजने होंगे। अब केवल कृषि व्यवसाय आधारित ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है।

## मंदिर-मस्जिद के विवाद में उलझा देश

#### —शाजिवा इल्मी—

समेल में हुई आगजनी की घटना के बावजूद, सगोचर न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जाने के बाद निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। अजमेर में एक स्थानीय अदालत द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करने के निर्णय से एक अन्य धार्मिक फर्म को श्रद्धा का खतरा है। सूफी संत मोहनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लीचे एक शिव मंदिर होने का दावा करते हुए दरिया में सर्वेक्षण और अजमेर पंचायत पर हिंदुओं की पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता, हिंदू संत के विष्णु गुप्ता, जिनके पास झूठी शिकायतों का एक पैसा इतिहास है, ने दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने का तर्क दिया है। काश गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (एन.एस.एस.) के सरसंघचालक मोहन भागवत जी की बातों पर ख्यात दिया होता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने और हर दिन एक यात्रा विवाद शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

जून 2022 में, उन्होंने कहा था कि अब शानवाणी मस्जिद (वाराणसी) में मुझ बच रहा है। इतिहास है, जिसे हम बदल नहीं सकते। न ही इतिहास हमने नहीं बनाया है। न ही आज के हिंदुओं या मुसलमानों ने। यह उस समय हुआ जब इस्लाम आक्रमणकारियों के साथ भारत में आया था। आक्रमण के दौरान, प्रत्येकता चाहने वाले लोगों के धर्म को कमजोर करने के लिए मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। ऐसे हजारों मंदिर हैं। पिछले कुछ समय से अजमेर दरगाह कुछ कट्टरशायी समूहों के लिए विवाद का विषय रही है। यह कुछ ऐसे लोगों द्वारा हास्यास्पद दावों का विषय रही है जो स्पष्ट रूप से सूफी विचारधारा के इतिहास और मूल्यों को नहीं समझते हैं। बिंदुबद्ध यह है कि ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह को खंडाबुद्धों द्वारा उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना मुसलमानों द्वारा। दरगाह बाजार में 75 प्रतिशत से अधिक दुकानें और होटल हिंदुओं के स्वामित्व में हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सभी प्रधानमंत्रियों ने उस के अवसर पर पवित्र चांदर भेजी हैं।

बाराही मस्जिद, शानवाणी और संत के विवादों के बाद, अजमेर 2 सप्ताहों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व



के ताने-बाने पर सबसे नया तनाव है। हालांकि, जहां अन्य विवादित स्थल मस्जिद थे वहीं यह एक प्रसिद्ध सूफी दरगाह है। मस्जिद और दरगाह के बीच स्पष्ट अंतरों में से एक यह है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए ईबादत की जगह होती है जहां आस्तिक सज्जदा करते हैं, यानी अल्लाह को सज्जदा करते हैं, जबकि दरगाह वह जगह होती है जहां श्रेष्ठ सूफी संतों के लिए दरगाह बनाई जाती है। यह पहली बार नहीं है कि किसी सूफी दरगाह को खराब पहुंचा जा रहा है। सूफी संप्रदायों के विपरीतमाजी का रूढ़िवादी धर्मशास्त्र के विपरीतमाजी माना जाता है, यही कारण है कि सदियों से उन्हें सततया जाता रहा है।

सूफीवाद इस्लामी विचार का तपस्वी, रहस्यवादी रूप है, जिनके गुरु रूप से सना-सुनौ विमानन से पर, राजनीतिक सीमाओं, आर्थिक वर्ग, भाषाओं और धर्मों तक फैले हुए हैं। अपने बुढ़ते प्रभाव क्षेत्र से खतरें में पड़े सूफीवाद और उनकी दरगाहों पर धार्मिक इस्लामीकरण के सभी स्थलों ने हमला किया है। वहाबी, देवबंदी, सूफीवादी और इस्लामी पुनरुत्थानवादी संतों और सूफी श्रेष्ठों की पूजा को 'बहुदेववादी मानते हैं। अफगानिस्तान और ईरान से लेकर तुर्की और आज के पाकिस्तान तक, सूफी संप्रदायों को अभी भी भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत में भी देवबंदी संप्रदाय ने अक्सर दरगाह वाली की खूबनादी की है, कई बार तो उन्हें धार्मिक वैधता देने के भी इंकार कर दिया है। यह मानना आसान है कि भारत में आखिरी सूफी श्रेष्ठ संप्रदाय काशी का कट्टरशायी शरीफ उददीन ने मरवा दिया था।अजमेर, जहां बादशाह अकबर ने 17 से ज्यादा बार यात्रा की थी, उनके पड़ोसी द्वारा शिक्के का जन्मनाशक भी था, जो शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। हालांकि, दारा शिकोह को 1659 में फांसी दे दी गई थी।

अपने भाई औरंगजेब के आदेश

पर, बमुरिश्कल 2 साल बाद, दारा शिकोह के कठोरी विश्वासघात सस्पन्द का औरंगजेब के आदेशियों ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर काटन कर दिया था। सरसद को ईशान्वित के आसपास फैला दी गई थी, लेकिन उन्हें आज भी संत माना जाता है और आज मस्जिद के पास उनका मजार सूफी तीर्थयात्रा का एक श्रेष्ठ प्रयास के स्थान बनी हुई है। याचिका रहस्यवादी दारा शिकोह की महानामा साहित्यिक विवरण सिर-ए-अकबर या महान रहस्य थी, जो उपनिषदों का फायसी अनुवाद था, यह उनका मानना-उल-बहरीन या 'दो सुन्नदों का संशम था, जो एकदम पर पहला गंध था, जिसने एक प्रकट सफलता में सूफीवाद और वेदों के बीच सम्मनाती की खोज की। मेहन भागवत की सलाह को गंभीरता से सुनने के अलावा विनियु गुप्ता जैसे लोग दारा शिकोह की इस अंतर्दृष्टि से सी सीध सज्जते हैं कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कोई बुनियादी अंतर नहीं है।

उन्हें यह देखकर अचर्य हुआ कि प्रत्येक धर्म के विद्वान अपने-अपने धर्मी की संरचनाओं में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें इस एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सत्य का एहसास नहीं हुआ। शायद सबसे महत्वपूर्ण यह कि दोनों धर्म मूलतः एक ही हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि उन्हें इस अंतर्दृष्टि से अवगत कराया जाए। समावेशी विकास के पथ पर अक्सर भारत सांभ्रादयिक उथल-पुथल और धार्मिक संघर्षों से मुक्त हो सकता है। धार्मिक संघर्ष आधुनिकता प्रगति और आधुनिकता के विकास के विपरीत है। अस्सय धार्मिक देशों को रोचना होगा, इससे पहले कि यह हमारी सामाजिक लोकाचारों की सहज आज यास्फिकता को नष्ट कर दे। कल के भारत को अंधविश्वास और पट्टी से उतारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (लेखिका भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।) (सामार एक्सप्रेस न्यूज)

**प्यार और दीवार गिराई**

छप्पर को गिराने लगे जब उसने राकेश को तभी लोग धुंकाए होकर अपभ्रंश करने लगे। यही नहीं उसने लात-कुत्ता और मुक्का-थप्पड़ से समझकर पीटा। इससे बाद सभी लोग लाठी-डंडे बल्लम से दीवार व छप्पर गिरा रहे थे। उसने जब मदद की गुहार लगा तो गांव के तनमा मौके की ओर दौड़े।

इस पर विपश्यनी जी से मारने की दस्ते हुए भाग निकले। पीछित रविवार केद शक ही कहोबा पुलिस चौकी को इस मामले की सूचना दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाकसाथ अतृप्त आदमी ने बलात्क प्रार्थना प्रत भिता है दोनों पक्ष को थाने पर बुलाया गया है। जांके के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अदालत के हवाले किया गया।  
 २०. २०११